

## सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई)

### प्रेस रिलीज

- भारत एक आर्थिक महाशक्ति अवश्य है लेकिन संभावित प्रदूषण अब बेहिसाब हो चला है और सी एस ई भारत के छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों पर चर्चा कर रहा है।
- भारत के लघु और मध्यम उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण पर सीएसई की कार्यशाला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग संघों आदि सहित प्रमुख खिलाड़ियों को एक साथ लाकर इस क्षेत्र के लिए एक रोडमैप का सुझाव देती है।
- सुनीता नारायण: "आज की जलवायु परिवर्तन-तनावग्रस्त दुनिया में, यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह क्षेत्र स्वच्छ ईंधन, सामान्य दहन सुविधाओं और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल शुरू करे एवं उत्सर्जन को नियंत्रित करने और बुनियादी ढांचे की सुविधाओं में सुधार करके परिवर्तन की दिशा में गंभीरता से काम करे। "

नई दिल्ली, 27 मई, 2022: भारतीय उद्योग के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है। भारत की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र द्वारा निर्भाई गई इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, शहरों और क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता में इसके योगदान का शायद ही कभी मूल्यांकन या विश्लेषण हुआ हो।

हालांकि आंकड़े और अनुमान बेहद अविश्वसनीय हैं, 2011 (तत्कालीन) योजना आयोग की रिपोर्ट ने अनुमान लगाया था कि उद्योगों से कुल उत्सर्जन के 70 प्रतिशत हिस्से के लिए एमएसएमई उद्योग ही जिम्मेदार हैं।

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) उन कुछ संस्थाओं में से एक है जो इस क्षेत्र द्वारा वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा: "छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों में औद्योगिक उत्सर्जन में योगदान देने वाले सबसे आम उत्प्रेरक पुरानी और अप्रचलित तकनीक, खराब बुनियादी ढांचा और ईंधन के रूप में कोयले पर उनकी निरंतर निर्भरता है।"

नारायण आज यहां सीएसई द्वारा आयोजित एक दिवसीय हितधारक कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं, जिसमें 'लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण रणनीति' विषय पर चर्चा की गई थी। यह आयोजन प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, औद्योगिक संघों, एमएसएमई विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और भारत भर के सलाहकारों एवं अधिकारियों को प्रदूषण में इस क्षेत्र के योगदान पर चर्चा करने और उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक मंच था।

अनुमिता रॉयचौधरी, कार्यकारी निदेशक-रिसर्च एंड एडवोकेसी, सीएसई ने कहा: "कई हालिया स्रोत विभाजन अध्ययनों के अनुसार, छोटे और मध्यम स्तर के औद्योगिक क्षेत्र वायु प्रदूषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में तेजी से सामने आ रहे हैं। हमने पाया है कि यह क्षेत्र कई समस्याओं से ग्रस्त है - विश्वसनीय डेटा की कमी, प्रदूषणकारी ईंधन के उपयोग और अक्षम छोटे बॉयलरों से लेकर स्वच्छ प्रौद्योगिकी की कमी तक।"

इस विषय पर सीएसई के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए, निवित कुमार यादव, कार्यक्रम निदेशक, औद्योगिक प्रदूषण, सीएसई ने कहा: "दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक वायु प्रदूषण के आकलन पर सीएसई का 2020 का अध्ययन <https://www.cseindia.org/report-on-assessment-of-industrial-air-pollution-in-delhi-ncr-10156> जिसमें अलवर, भिवाड़ी, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और सोनीपत के सात प्रमुख औद्योगिक जिलों को कवर किया गया था, ने अनुमान लगाया था कि इन इलाकों में 1.4 मिलियन टन तक कोयले की खपत होगी। इन क्षेत्रों में अधिकांश उद्योग छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग थे।"

सीएसई के अनुसार, इन उद्योगों को स्वच्छ ईंधन और सामान्य दहन सुविधाएं अपनाने, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल एवं उत्सर्जन को नियंत्रित करने और सुधार के लिए एक स्थायी भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और सक्षम वातावरण की आवश्यकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और कार्यशाला में वक्ताओं में से एक प्रशांत गर्गव ने इस स्थिति में उद्योग संघों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "उद्योगों के बीच सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में उद्योग संघों की महत्वपूर्ण भूमिका है।"

एक 'हरित', स्वच्छ एमएसएमई क्षेत्र के लिए रोडमैप: कुछ सुझाव

कॉमन बॉयलरों का प्रयोग: यादव कहते हैं, बड़ी संख्या में छोटे बॉयलरों का उपयोग करने के बजाय एक स्थान पर बसे उद्योग एक कॉमन बॉयलर स्थापित कर सकते हैं (इस विषय पर सीएसई की रिपोर्ट देखें: <https://www.cseindia.org/replacement-of-smal-biolers-with-common-steam-boilers-in-industrial-areas-10280>) सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार - (औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य स्टीम बॉयलरों के साथ छोटे बॉयलरों का प्रतिस्थापन: एक व्यवहार्यता मूल्यांकन ) - हर उद्योग के लिए एक छोटे बॉयलर की जगह एक कॉमन बॉयलर के प्रयोग से औद्योगिक वायु प्रदूषण में 65 से 70 प्रतिशत की कमी और कोयले की खपत में 25 से 30 प्रतिशत की कटौती संभव है।

पार्थ कुमार, प्रोग्राम मैनेजर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, सीएसई के अनुसार: "कॉमन बॉयलर्स दोनों उद्योगों एवं नियामक एजेंसियों के बोझ को कम करने के साथ ही साथ स्थानीय वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं।"

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस नारायणन ने एक चेतावनी दी: "हमें नीतिगत ढांचे में कॉमन बॉयलरों के बारे में सोचने की जरूरत है। कानून में कुछ बदलाव के कारण कॉमन बॉयलरों में आज किया गया निवेश कल बेकार नहीं जाना चाहिए।"

ईट भट्टों में प्रौद्योगिकी परिवर्तन : ईट भट्टा क्षेत्र में, एफसीबीटीके के स्थान पर ज़िगज़ैग का प्रयोग वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दिल्ली-एनसीआर सीपीसीबी और पूर्ववर्ती पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) जैसी एजेंसियों के समन्वित प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक ईट भट्टों को क्लीनर ज़िगज़ैग तकनीक में स्थानांतरित कर दिया गया है। .. यादव कहते हैं: "ज़िगज़ैग तकनीक के प्रयोग से कोयले की खपत 20-30 प्रतिशत कम हो जाती है और प्रथम श्रेणी की ईटों का प्रतिशत 80 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है (ईट भट्टों पर सीएसई की रिपोर्ट यहां देखें <https://www.cseindia.org/emissions-monitoring-of-brick-kilns-9387>)"

आशुलोपी अथवा फ़्यूजिटिव उत्सर्जन को नियंत्रित करना: सीएसई ने उद्योगों से होनेवाले फ़्यूजिटिव उत्सर्जन की समस्या का अध्ययन किया है - विशेष रूप से, राजस्थान में खनिज पीसने वाला क्षेत्र और दिल्ली-एनसीआर में स्टोन क्रेशर क्षेत्र। यह पाया गया है कि अधिकांश इकाइयाँ संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही हैं। सीएसई ने सिफारिश की है कि मिनरल ग्राइंडिंग, स्टोन क्रेशर और अन्य ऐसे फ़्यूजिटिव उत्सर्जन वाले धूल-गहन उद्योगों के लिए विशेष क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। यादव कहते हैं कि यह राज्य के दिशा-निर्देशों में आवश्यक बदलाव की भी सिफारिश करता है जो वर्तमान में ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत व्यापक नहीं हैं - उन्हें और अधिक विस्तृत और कार्यान्वयन योग्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

सीएसई के शोधकर्ता बताते हैं कि स्टोन क्रशर के लिए इस्तेमाल में लायी जानेवाली वेट सप्लेशन प्रणाली जमीन पर विफल हो गई है - इसलिए, धूल निष्कर्षण प्रणाली को क्षेत्र द्वारा अपनाया जाना चाहिए (इस विषय पर सीएसई की रिपोर्ट यहां देखें : <https://www.cseindia.org/implementation-challenges-of-environmental-guidelines-in-the-stone-crusher-industry-11164>)

कपोला-आधारित भट्टियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना: एमएसएमई क्षेत्र का एक अन्य प्रमुख घटक - फाउंड्री उद्योग, प्रदूषणकारी और पुरानी कोक-ईंधन वाली, कपोला-आधारित भट्टियों का उपयोग करता है - जयपुर में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में सीएसई के पायलट अध्ययन ने इन भट्टियों के लिए एक फेज-आउट योजना की सिफारिश की है। (यह अध्ययन रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी)।

नारायण ने कहा: "73वां राष्ट्रीय सैंपल सर्वे (2015-16) हमें बताता है कि भारत के एमएसएमई क्षेत्र में 63 मिलियन इकाइयां हैं जिन्होंने 111 मिलियन नौकरियां पैदा की हैं - एक ऐसा क्षेत्र जिसमें इस तरह का पैमाना है, स्वाभाविक रूप से एक विशाल पर्यावरणीय पदचिह्न छोड़ेगा। सीएसई में, हमारा प्रयास इस क्षेत्र को "हरित", स्वच्छ तरीके से काम करने में मदद करने के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्पों का पता लगाने का रहा है। आज की कार्यशाला उसी प्रयास का एक हिस्सा है - हमें उम्मीद है कि इससे समन्वित तरीके से आगे बढ़ने के तरीकों पर आम सहमति बनाने में मदद मिलेगी।"

इस विषय में और जानकारी एवं साक्षात्कार आदि के लिए कृपया सीएसई मीडिया रिसोर्स सेंटर की सुकन्या नायर से संपर्क करें: [sukanya.nair@cseindia.org](mailto:sukanya.nair@cseindia.org), 8816818864